Besides, 34 commodities have been identified for extreme focus in sectors with potential for a quantum increase in exports.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Scientific mining by coal companies

*378. SHRI SUNIL BASU RAY :
SHRI SUKOMAL SEN :

Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether it is a fact that coal mines were nationalised in 1972 for scientific mining;

(b) if so, whether it is being followed by Coal India units like BCCL;

(c) whether any breach in this regard has come to the notice of Government; and

(d) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SH. AJIT KUMAR PANJA) : (a) The exploitation of labour, scant regard for conservation, safety and scientific mining, stagnation of production and lack of investment in the private sector were the main factors leading to the nationalisation of coal industry.

(b) Yes, Sir. Scientific mining has been resorted to in both underground and opencast mines of Coal India Ltd. and its subsidiaries including BCCL by way of introducing appropriate modern mining technologies/equipment in opencast and underground mines.

(c) and (d) The constraints experienced in the operation of such technologies include inadequate capacity of equipments, difficulties in spares availability, mis-match of equipments, inadequate and interrupted supply of power problem of ground control & related geo-mining problems.

कोयला केन्द्रों पर सरकार का नियंत्रण होने से कोयले की आपूर्ति पर पड़ा प्रतिकूल प्रभाव

*379. **श्री राम सिंह राठवा :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा कोयला केन्द्रों को अपने नियंत्रण में लिए जाने के बाद से ताप विद्युत केन्द्रों और कारखानों के लिए कोयले की आपूर्ति पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति का विद्युत उत्पादन पर विशेष रूप से गुजरात और उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार पांजा) : (क) इस संबंध में माननीय सदस्य का आशय कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उसके कार्य-निष्पादन से है । 1972-73 के दौरान अखिल भारतीय उत्पादन जो कि लगभग 77 मिलियन टन था, 1991-92 में बढ़कर 229 मिलियन टन हो गया तथा उसके 1992-93 में बढ़कर 238 मिलियन टन होने की संभावना है । वर्ष 1972-73 में किए गए 70 मिलियन टन के प्रेषण की तुलना में यह वर्ष 1991-92 में बढ़कर 218 मिलियन टन हो गया । वर्ष 1992-93 में 233 मिलियन टन प्रेषण होने की संभावना है । वर्ष 1991-92 के दौरान विद्युत क्षेत्र को 137 मिलियन टन कोयले का प्रेषण किया गया जिसके 1992-93 के दौरान बढ़कर 150 मिलियन टन तक पहुंच जाने की संभावना है ।

(ख) और (ग) गुजरात तथा उत्तर प्रदेश के विद्युत बोर्डों से किए गए कोयले की आपूर्ति की गुणवत्ता के बारे में कुछ शिकायत प्राप्त हुई हैं । ये शिकायतें

कोयले के लदान स्थल से प्रेषण किए जाने के पश्चात् प्राप्त होती है । गुणवत्ता की समस्या मुख्य रूप में ग्रेड में कमी होने, कोयले में अपशिष्ट सामग्री के होने तथा कोयले का बड़े आकार में होना है । । उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले कोयले की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) फीडर ब्रेकरों एवं कोयला रखरखाव संयंत्रों की स्थापना किए जाने की एक कार्रवाई योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को समान आकार के कोयले की आपूर्ति किए जाने को सुनिश्चित किया जा सके ।

(2) कोयले का लदान किए जाने के समय पत्थरों को पृथक किया जा रहा है ।

(3) कोयला रखरखाव संयंत्रों में कंकड़ और पत्थरों को उठाने के लिए स्लो मूविंग पिकिंग बेल्ट्स उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

(4) कोयला लदान के समय बेहतर पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि रेलवे साईडिंग पर कार्यरत श्रमिकों, पर्यवेक्षकों एवं अधिकारियों के मध्य गुणवत्ता संबंधी जागरूकता को विकसित किया जा सके और कोयले की गुणवत्ता बनाई रखी जा सके ।

(5) रेल/सड़क साईडिंग (लदान स्थलों पर) पिटहैड पर गुणवत्ता तथा मात्रा का निर्धारण किए जाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं और अभी भी इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बाद में खरीददारों तथा विक्रेताओं के बीच होने वाले विवादों से उत्पन्न किसी तरह की दिक्कतों से बचा जा सके ।

Bidi workers in the country

*380. SHRIMATI VEENA VERMA :
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE :

Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) what is the number of bidi workers in the country, state-wise; at present;

(b) what is the number of bidi workers who are covered by E. P. F. Scheme;

(c) what is the amount of Central Excise collected from the bidi industry during the last five years;

(d) what is the number of bidi workers benefited from the Bidi Workers Welfare Scheme; and

(e) what is the number of unregistered bidi manufacturers and the total number of workers employed by them ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) (a) & (b) A list as statement-I is laid on the Table of the House (*See* below).

(c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) A list as statement-II showing the number of beneficiaries under different Welfare Schemes of the Bidi Workers' Welfare Fund is laid on the Table of the House (*See* below).

(e) Data on unregistered bidi manufacturers and workers employed by them are not maintained by the Government of India,